Publication: The Economic Times (Hindi) **Date: Thursday, 03rd July, 2015**

Edition: Delhi

सरकारी बॉन्ड में निवेश से घटेगा ULIP का अट्रैक्शन

| प्रीति कुलकर्णी & संकेत धनोरकर | मुंबई |

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लांस (ULIP) के इनवेस्टर्स के रिटर्न और इनवेस्टमेंट चॉइस में कमी आ सकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने यूलिप में जमा फंड का कम से कम 25 पर्सेंट सरकारी बॉन्ड में लगाने का प्रपोजल दिया है।

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर एम विशाखा का कहना है, 'सभी एसेट क्लास में इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। सरकारी बॉन्ड में मिनिमम इनवेस्टमेंट लिमिट फिक्स करना इस रिसर्च बेस्ड नजरिये के उलट होगा। इससे कस्टमर्स को मिलने वाली चॉइस में कमी आएगी।'

अभी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 50 से 60 पर्सेंट यूलिप हैं। इसके जरिए हासिल होने वाले प्रीमियम का इनवेस्टमेंट 90 पर्सेंट इक्विटी में होता है। इरडा के प्रपोजल मान लिए जाने पर पॉलिसीहोल्डर्स के ऑप्शंस घट जाएंगे। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ क्षितिज जैन के मुताबिक, 'ड्राफ्ट नॉर्म्स से कस्टमर्स को मिल रही फ्लैक्सिबिलिटी घटेगी।' सभी यूलिप इक्विटी और डेट फंड ऑप्शन ऑफर करते हैं। इसमें प्योर इक्विटी, डेट और बैलेंस्ड फंड्स वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है। जैन कहते हैं, 'यूलिप पहले से ही हाइब्रिड फंड ऑफर कर रहे हैं जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर लिमिटेड होता है। कस्टमर्स को 100 पर्सेंट इक्विटी फंड्स में इनवेस्टमेंट करने की च्वाइस होनी चाहिए।'

इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने ULIP में जमा फंड का कम से कम 25% सरकारी बॉन्ड में लगाने का प्रपोजल दिया

यूलिप का पोटेंशियल खराब करने वाला यह कदम तब उठाया जा रहा है, जब व्यापक रेगुलेटरी चेंज और 2010 से 2013 के बीच मार्केट की खराब हालत से पस्त ये इंश्योरेंस-कम-इनवेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स के बाद वापस कर रहे हैं। इसके बारे में इकनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले 1 जुलाई 2015 को खबर दी थी। 2013 के बाद से इक्विटी मार्केट में तेजी आने पर यूलिप में ठीकठाक रिवाइवल होने लगा। फिस्कल ईयर 2014-15 के दौरान यूलिप में फ्रेश प्रीमियम इनकम पिछले फिस्कल ईयर के मुकाबले 40 पर्सेंट बढ़कर 13250 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान यूलिप से हासिल होने वाली कुल रकम 15 पर्सेंट बढ़कर 41,565 करोड़ रुपये हो गई। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के डेटा के मुताबिक, मार्च 2015 में कुल इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 5.26 लाख करोड़ रुपये से 20 पर्सेंट बढ़कर 6.3 लाख करोड़ रुपये हो गया था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) का प्रपोजल यूलिप की राह का रोड़ा बन सकता है। यह 2010 के बाद एक के बाद एक कई रेगुलेशंस के चलते पहले से सुस्त इंडस्ट्री का मूड खराब कर सकता है। एडवाइजरी फर्म आउटलुक एशिया कैपिटल के सीईओ मनोज नागपाल ने कहा, 'यह प्रस्ताव अवनति के रास्ते पर ले जाने वाला है। मार्केट लिंक्ड प्रॉडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उससे मार्केट की तरह ही रिटर्न मिले।' उन्होंने सरकारी सिक्योरिटीज में कम से कम 25 पर्सेंट इनवेस्टमेंट को बैंक के एसएलआर जैसी रिक्वायरमेंट करार दिया है।

उन्होंने कहा, 'मार्केट लिंक्ड प्रॉडक्ट में बैंकिंग जैसा काम नहीं कर सकते।' इंश्योरेंस कंपनियों को डर है कि ऐसे प्रोविजन से वे म्यूचुअल फंड्स की बराबरी में आएंगी। इससे इनवेस्टर्स यूलिप के बजाय म्यूचुअल फंड्स में इनवेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को लगता है कि MF को बढ़त हासिल होगी क्योंकि यूलिप फंड मैनेजर से इनवेस्टमेंट के फैसले लेने की आजादी छिन जाएगी। मनीवक्सं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फाउंडर नसरीन मामजी कहती हैं, 'एसेट एलोकेशन पूरी तरह से फंड मैनेजर का काम होना चाहिए। यह फैसला कोई और नहीं ले सकता कि फंड का पैसा कहां लगाया जाएगा। इसलिए यूलिप्स को म्यूचुअल फंड्स जैसे कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा।' लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि यह सेक्टर और पॉलिसीहोल्डर्स के लिए परेशानी पैदा करने वाला है भले ही प्रपोजल अपने मौजूदा फॉर्म में पास हो जाए। IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इनवेस्टमेंट ऑफिसर अनीश श्रीवास्तव कहते हैं, 'इससे यह पक्का होगा कि पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा है। पॉलिसीहोल्डर्स को ऊंचा रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा बलिदान नहीं देना होगा।'

A Joint Venture of
Bank of Baroda Legal & General Andhra Bank